नकदी रहित भारत (कैशलेस इंडिया)

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्र सरकार ने 8 नवंबर, 2016 को 500 रुपये एवं 1000 रुपये की पुरानी मुद्रा का अवमूल्यन कर दिया और साथ ही नकदी रहित भारत (कैशलेस भारत) के स्वप्न को साकार करने की दिशा में सरकार सतत् प्रयासरत है। यह जानते हुए भी कि भारत की अर्थव्यवस्था विश्व की कई अन्य देशों की अर्थव्यवस्था की तुलना में नकदी पर अधिक निर्भर है, सरकार द्वारा उच्च मूल्य वर्ग की मुद्रा का अवमूल्यन वास्तव में एक साहसिक कदम था। अचानक, लिए गए इस निर्णय की वजह से बाजार में नकदी की भारी कमी हो गई और लोगों को आवश्यक वस्तुएं खरीदने में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा क्योंकि बैंको एवं एटीएम से नई मुद्रा बहुत ही कम मात्रा में उपलब्ध हो पा रही थी उसे भी पाने के लिए लोगों को रात-दिन लंबी-लंबी कतारों में खड़ा रहना पड़ा।

निष्कर्ष: हालांकि, इस कदम का लाभ अब प्राप्त होना शुरू हो गया है और ज्यादा से ज्यादा लोगों ने डिजिटल मुद्रा में लेन देन शुरू भी कर दिया है। भारत धीरे-धीरे नकदी केंद्रित अर्थव्यस्था से नकदी रहित अर्थव्यवस्था (कैशलेश इकॉनमी) की तरफ लगातार बढ़ रहा है। डिजिटल लेनदेन का पता आसानी से चल जाता है जिस वजह से सबके लिए करों का भुगतान करना अनिवार्य हो जाएगा और काले धन के संचलन के सभी रास्ते बंद हो जाएंगे। पूरा देश लेनदेन के प्रक्रिया के आधुनिकीकरण के दौर से गुजर रहा है और इस वजह से ई-भुगतान सेवाओं में अभूतपूर्व प्रगति हो रही है। कारोबारियों की एक बड़ी संख्या और यहां तक कि सड़क के किनारे सामान बेचने वाले फुटकर विक्रेताओं ने भी अब इलेक्ट्रॉनिक भुगतान स्वीकार करना शुरू कर दिया है और इस तरह से वे भी सभी लोगों को तेजी से नकदी रहित लेन-देन प्रणाली अपनाने के लिए प्रेरणादायक सिद्ध हुए हैं।